currency notes which are released after circulation and are burnt daily by the Reserve Bank of India. The answer was given in terms of the notes cancelled for destruction daily as the number of notes burnt daily was not readily available. The notes cancelled during any given period cannot always be burnt in the same period (for instance, if some incinerators are out of order) so that there may at times be a carry-over of cancelled notes awaiting destruction by fire. As stated earlier, over the twelve-months period preceding the date of the original answer, the daily average of notes cancelled comes to 69,81,953. For the same period the daily average of notes burnt comes to 74,59,645.

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 471 DATED 28TH JULY, 1966 REGARDING PERSONS EMPLOYED AT ASHOKA HOTEL

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): In reply to Unstarred Question No. 471 answered on the 28th July, 1966 relating to the death of an electrician in the Ashoka Hotels Limited, I had stated with reference to parts (c) and (d) of the question that compensation for leave due amounting to Rs. 340.75 has been paid to the wife of the deceased. It has now been found that there is an inaccuracy in the answer given. The amount of compensation for leave due to the deceased is Rs. 83.60 and not Rs. 340.75. Item (i) under the answer to parts (c) and (d) of the above mentioned question should, therefore, read as under:—

> "Gratuity of Rs. 210.00 and compensation for leave due amounting to Rs. 83.60 have been paid to the wife of the deceased."

12.15 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

DAMAGE DUE TO FLOODS IN BIHAR

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

> "The damage caused by the recent floods in Bihar".

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): There had been heavy rains in Nepal Hills bordering Bihar and in the north-eastern districts of Darbhanga, Muzaffarpur, Champaran and Saran in the last week of August. This resulted in a rush of large quantities of water in the rivers of these districts, causing submersion of large tracts of land. The rivers mainly affected are Kamla Balan, Bhutahi Balan, Bagmati, Lakhandei, Burhi Gandak and the Gandak. Breaches have been reported in the Kamla Balan and Khiroi embankments in Darbhanga district, Adhwara embankments in Sitamarhi sub-Division of Muzaffarpur, Bherihari embankment in Champaran and Saran embankment of Chapra. Serious erosion has taken place in the area adjoining Sikhanderpur in Muzaffarpur town on the Burhi Gandak river, causing a breach. The floods have disrupted road and rail communications in the area.

The assessment of the damage due to these floods is still being made, but according to information collected so far by the State Government, an area of 23.7 lakh acres has been affected, including a cropped area of about 15.5 lakh acres. The approximate value of the crops damaged is estimated by the State Government at Rs. 25 crores. A population of 3.6 million is reported to have been affected. Four persons are reported to have lost their lives.

The State Government have opened a number of relief Centres. A large number of boats has been deployed for rescue operations. Cash grants and loans are being given to the people affected by floods. Fair price shops have been opened and medical and other assistance is being rendered to the people. The Prime Minis-

[Shri Bibhuti Mishra]
ter has sent a cheque for Rs. 50,000 for flood relief in the flood-affected areas.

The present floods have been most unfortunate particularly as the State, after a prolonged drought, was hoping for a good harvest.

On receipt of information regarding the severe floods, I proceeded to Bihar along with my colleague, Dr. K. L. Rao and made an aerial inspection of the flood affected areas on the 30th August. We also inspected the serious erosion going on at Muzaffarpur. Five Members of Parliament and officials of the Ministry of Irrigation and Power and Central Water and Power Commission were also in the party. I had also discussions with the Chief Minister and other Ministers and officials of the State Government, regarding the flood situation and the measures to be taken.

A number of flood protection works have already been executed, but much more remains to be done. The experience of this year's floods will have to be studied and suitable remedial measures taken. There is no doubt that drainage conditions in North Bihar require improvement. An Expert Committee has already been appointed by us to go into this problem thoroughly.

In the discussions with the State Chief Minister and others, the immediate measures to be taken to deal with the situation have been indicated. The State Government have indicated that they would require Rs. 10 crores for their flood and drought relief operations. They have also indicated their requirements of foodgrains in the coming months and of supply of seed. The requests of the State Government are being considered.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, श्री फखरुद्दीन अहमद, राव साहब और इंडियन ऐयर फोर्स के जवानों को धन्यवाद देते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि छित्तौनी बांध के टूटने से उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ और फिर मोतीहारी शहर में सिकाहना नदी का पानी पाया गया और इस सिकारना नदी के कमांडेंड एरिया में फसलों की बरबादी और घरों की बरबादी हुई। इस के अलावा बागमती नदी के कमांडेंड एरिया में क्षति हुई फिर कोसी नदी की बाढ़ से कोसी नदी के कमांडेंड ऐरिया में भी क्षति हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि आयन्दा से इस बाढ़ को रोकने का कोई स्थायी इंतजाम किया जा सके।

श्री फखरुद्दीन अहमद : इन चीजों को हम ने देखा। सब से पहला सवाल यह पैदा होता है कि जो एम्बैंकमेंट बनाये गये हैं उन को मजबूत बनाना चाहिये और ऊंचे करना चाहिये। ज्यों ज्यों साल गुजरते जाते हैं, पानी के साथ जो सिल्ट आती है उस से सर्फेस ऊंची हो जाती है। उन की हर साल रिपेअर्स न हों तो जो बड़ी बाढ़ आती है उस से उन में ब्रीचेज होती हैं और उस की वजह से फ्लड वगैरह होते हैं। हम ने सोचा है कि किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट उन तमाम एम्बैंकमेंट्स को ठीक करने का प्रोग्राम हाथ में ले और उन से जो मदद ली जा सकती हो वह ली जाये।

श्री का० ना० तिवारी (बगहा) : स्टेटमेंट में दिया गया है कि :

> "The State Government have indicated that they would require Rs. 10 crores for their flood and drought relief operations. They have also indicated their requirements of foodgrains in the coming months and of supply of seed. The requests of the State Government are being considered.

आज अभी रेडियो में खबर आई है कि 165 करोड़ रु० का नुक्सान हुआ है। मंत्री महोदय को चीफ़ मिनिस्टर ने यह भी बतलाया कि करीब 25 लाख टन से ले कर 33 लाख टन फूड ग्रेन्स में कमी होगी। तो वहां से लौट कर

आने पर उन की मांग पर मंत्री महोदय ने क्या कार्रवाई की है ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : यहां आने के बाद मैंने अपना इन्स्पेक्शन नोट प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है और उन से कहा है कि फौरन स्टेट गवर्नमेंट को, जैसी उन की 5 करोड़ रु० की मांग है फ्लड रिलीफ के लिये, उतने रुपये **ऐडहाक बेसिस** पर भेज दिये जायें, और जो उनके फूड मिनिस्टर ने 2 लाख टन फी महीने के हिसाब से तीन या चार महीने के लिये मांग की है, उस का इन्तजाम किया जाये । साथ ही गेहूं बोने के लिये जिस अच्छे बीज की जरूरत है वह सितम्बर के पहले पहुंचा दिया जाये ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अब सरकार की समझ में यह बात आई है कि चूंकि हमारी वन सम्पत्ति कट गई है इसलिये एक दम बाढ़ें आ जाती हैं । पहले जो करोड़ों की तादाद में दरख्त थे वह इस बाढ़ को रोकते थे । देश में चौथाई लैंड अनकल्टिवेबल कर दी गई है क्योंकि ट्रैक्टर हैं नहीं और बैलों की कमी है । डा० राम मनोहर लोहिया ने पांच साल पहले आवाज लगाई थी कि अन्न सेना कायम की जाये और एक इंच जमीन भी बगैर टिलिंग के न रहे। चूंकि चौथाई जमीन बगैर टिलिंग के रह जाती है और पानी जज्ब नहीं होता है इसलिये एक दम से बाढ़ें आ जाती हैं । तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में गौर करेगी कि कोई जमीन बगैर टिलिंग के न रहे और कोई पेड़ नये तरीके से काटा न जाये ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : वनों की बाबत मैं कहना चाहता हूं कि जो एम्बैंकेमेंट बनाये गये हैं उन से बहुत हद तक जो फ्लड आते हैं वह रुक जाते हैं । इसके साथ साथ बहुत सी जगहों पर डिटेंशन रिजर्वायर वगैरह बन रहे हैं और जहां जहां बाढ़ें आती हैं उन से उनका कुछ प्रोटेक्शन होता है । पहले जिस तरह से फ्लड आया करते थे उनसे बहुत हद तक कमी हो गई है । लेकिन यह बहुत बड़ा काम मुल्क में है जहां इतनी बड़ी २ नदियां हैं और उसके लिए बहुत रुपये की जरूरत है । जितनी जल्दी हम मुल्क को इन तमाम मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, उतनी यह चीजें हमारे सामने आती हैं और उनकी वजह से काम बहुत आगे नहीं बढ़ सका है ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष बिहार में जो बाढ़ आई उस में इस से पहले जो बड़ी बाढ़ आई थी उस की अपेक्षा क्या ज्यादा फ़सल नष्ट हुई और क्या ज्यादा जमीन प्रभावित हुई, क्या ज्यादा जानवर बहे या मरे । यदि हां, तो फिर इसे रोकने के लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया है और इस बाढ़ को रोकने के लिए उस का क्या प्रोग्राम है ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : मुझ से कहा गया कि इस दफे जो सैलाब आया वह पिछले सैलाब से ज्यादा इन्टेन्सिव था, ऐक्स्टेन्सिव नहीं था । इसको रोकने के लिए सिवा इसके कि हम डिटेन्शन डैम बनायगे और जो म्वैकमेंट हैं उन को पक्का करायें और कोई रास्ता नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव : मैं ने पूछा था कि कितनी जमीन बाढ़ की लपेट में आई । क्या मंत्री महोदय इसके कोई आंकड़े बतायेंगे कि कितनी जमीन जलमग्न हुई ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह बाढ़ एक्स्टेन्सिव नहीं हुई है, इंटेंसिव हुई है । जहां तक जमीन के पानी में आने का सवाल है, मुकम्मिल रिपोर्ट मिलने पर सारी चीजों का पता चलेगा ।

श्री रामसेवक यादव : मंत्री महोदय वहां उड़ कर बाढ़ देखने गये थे । क्या

[श्री रामसेवक यादव]

उनको पता नहीं कि कितनी जमीन जलमग्न हुई और कितनी फ़सल नष्ट हुई ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर बिहार का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, क्या उसके लिये लगान वसूली, लेवी वसूली, तकावी की वसूली और कर्ज की वसूली आदि के जितने कानून हैं वह सारे स्थगित किये जायेंगे और क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस किस्म की सलाह राज्य सरकार को दी जायेगी ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट के करने का है कि कैसे रिलीफ़ वर्क किया जायेगा । जो लोग काम कर सकते हैं उनको मजदूरी वगैरह देने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने तकावी आदि के बारे में पूछा था ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह तो रिपोर्ट के आने पर ही कहा जा सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : आज सुबह मंत्री महोदय ने कहा कि कोसी नदी के बांधने का काम काफ़ी हो चुका है । इसके साथ साथ पिछले 19 वर्षों या 20 वर्षों से बांध वगैरह बनाने के लिये तीन सबब या तीन उद्देश्य बतलाये गये, अर्थात् सिंचाई और बिजली देना और बाढ़ों को रोकना । साथ ही यह भी साबित हो चुका है कि 19 वर्ष के काम के बाद भी जो बाढ़ें वगैरह आ रही हैं वह पहले के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही खराब हैं । क्या मंत्री महोदय एक मूल्यांकन करेंगे इन सारी योजनाओं का जिससे पता चले कि कहां गड़बड़ हो गई है । या तो यह जो बांध बनाये गये वह मस्नूई रहे या उनमें कोई खराबी रही । अगर मूल्यांकन अब तक नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, और वह क्या क्या तरीके सोच रहे हैं जिनसे यह समस्या हल हो ।

श्री फखरुद्दीन अहमद : मैं ने पहले भी बतलाया कि जब पानी चन्द बरसों के बाद कुछ ज्यादा होता है तो उसके साथ सिल्ट आती है और सतह ऊंची हो जाती है । अगर उसी के साथ साथ एम्बैंकमेंट ऊंचे न किये जायें तो चार, पांच बरस के बाद जो सैलाब आता है उससे बड़ा नुकसान हो जाता है । दूसरे यह कि इन बरसों में बिहार में करीब दो हजार से ज्यादा एम्बैंकमेंट बनाये गये हैं । उन एम्बैंकमेंट्स के रिपेअर के लिये हर साल जो रुपया चाहिये, उनको मजबूत करने के लिये, उस के स्टेट गवर्नमेंट के पास न होने से, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा सका है । इस लिये जब पानी जोरसे आता है तो कमजोर एम्बैंकमेंट टूट जाते हैं और इसकी वजह से बड़ा नुक्सान होता है । हम सोच रहे हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एम्बैंकमेंट मजबूत करने के लिए मदद दी जाये और जहां जहां डिटेंशन डैम की जरूरत है वह किस तरह से जल्दी से जल्दी बनाये जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि बिहार सरकार पैसे की कमी के कारण इतना सब इन्तजाम नहीं कर पाई । इस तरह से उन्होंने इस बाढ़ के लिये बिहार सरकार को दोषी ठहराया है । अगर मान लीजिये कि हम यहां पर यह सवाल उठाते तो इस सारे मामले में यह कहते कि प्रान्तीय सरकार दोषी है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक व्यवस्था दें कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल कर इस सारे सूबे को तबाह कर रही हैं क्योंकि कोई आकाश की तरफ से तो यह बात नहीं हुई, इनकी बदइन्तजामी के कारण हुई । अगर इन्तजाम ठीक होता तो बाढ़ इतनी खराब न हुई होती । इस सम्बन्ध में आप एक व्यवस्था दें कि क्या मंत्री महोदय को बिहार सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर के, उस को दोषी बना कर के अपने दोष से रिहा होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं कि किस का दोष है, तब फिर व्यवस्था कैसे दे सकता हूं ।

श्री फख्रुद्दीन अहमद : मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप क्या मंत्री महोदय को नहीं रोकेंगे । रोकना खाली हमारे लिये है । उन्होंने बिहार सरकार को दोषी बतलाया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है कि क्या कारण है । इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उन्होंने बिहार सरकार को दोषी बतालाया है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कौन सा सवाल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसलिए कि ये कहते हैं कि यह प्रान्तीय मामला है और बिहार सरकार को दोषी बता कर खुद अपने दोष से रिहा हो जाना चाहते हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : (दरभंगा) : बिहार में और सालों की तरह से इस बार भी बाढ़ आई है । बाढ़ की भीषणता इसलिए बढ़ जाती है कि नदियों के किनारे जो तटबन्ध बनाए गए हैं वे अक्सर टूट जाया करते हैं । पहले नदियों पर तटबन्ध नहीं बनाये जाते थे । पीछे गवर्नमेंट ने यह तय किया कि तटबन्ध बनाये जायें । उत्तर बिहार की हालत यह है कि हर बार इनके टूट जाने से बाढ़ की भीषणता पहले की अपेक्षा और भी बढ़ती जाती है । क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए तटबन्ध बनाने की जो नीति है उसको त्याग कर कोई और नीति अखत्यार की जाए ?

श्री फख्रुद्दीन अहमद : नीति तो वही होगी । लेकिन जैसा मैं ने कहा है हम एम्बैंक मेंट्स को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि ज्यादा पानी आने से वे न टूटें ।

Shri Hem Barua (Gauhati): Before putting a question, may I draw your attention to a very relevant thing? My original notice contained the words "floods in Assam and Bihar", but somehow or other I find, Assam is being blacked out completely from the List of Business. My State, Assam, is neglected. This shows how Assam is neglected by anybody who is somebody.

Mr. Speaker: Nobody; he might put his question.

Shri Hem Barua: May I put a question about Assam since the hon. Minister comes from Assam?

Mr. Speaker: If he can answer it, I will allow it.

Shri Hem Barua: I think, he can because he comes from Assam.

Mr. Speaker: He might put the question.

Shri Hem Barua: Since floods are a recurring phenomenon in the State of Assam devastating human and cattle population and lots of property, may I know whether Government are in a position to tell us (a) if they are contemplating any permanent measures to check recurring floods in Assam, and (b) whether as an interim measure they have adopted any step by way of warning the people before the floods come, by way of having rubber boats to rescue the marooned people and by way of having some buffer stocks of grains so as to offer them relief when they are subjected to floods?

Shri Fakhruddin Ahmed: So far as the first question is concerned, I think, I had an occasion of informing the hon. Member that after my visit when the first flood came in Assam in June; we have discussed the matter and

[Shri Fakhruddin Ahmed]

have taken very positive steps to have some permanent schemes for the purpose of relieving Assam from floods and the work is so gigantic that it cannot be achieved within a very short time. As I indicated to hon. Members, we have set up two investigation teams in order to make a thorough investigation within as short a time as possible, one in Cachar and the other in Brahmaputra Valley, for the purpose of investigating the question of setting up retention dams at Pagladia, Manas, Subansiri and Kopli in Brahmaputra Valley and at Barak in Cachar. As soon as the investigation report is available to us, we shall certainly take concrete steps to start the work within the Fourth Plan.

So far as the other two questions are concerned, we are also making some arrangement by which warning regarding floods can be given to the people in proper time.

So far as the question of keeping a stock of foodgrains is concerned, it had been our policy not only because of effects of floods but because we are on one side of the country where sometimes communication is very bad, for the past two or three years of maintaining a buffer stock of essential goods for two or three months. I think, the same position is still maintained by the Assam Government. I shall find out whether there has been any deviation from that policy. It is necessary that the stock should also be kept.

So far as the question of boats is concerned, I think, the hon. Member is aware that practically all over Assam where people know that floods come every year, a large number of people have their own boats.

Shri Hem Barua: Government must have their own boats also.

Shri Fakhruddin Ahmed: The Government also have for the use of their officers as also for relief measures some arrangement. But if it is found necessary that something more should be done in that behalf, I shall look into that.

Mr. Speaker: Shri P. C. Borooah.

Shri Hem Barua: May I submit, in this case, during the last floods I visited an area in Nalbari and the people were marooned there in the villages for three days and women gave birth to children in their houses and they could not be rescued because you did not have a single boat and the one boat that you had was utilised by officers?

Mr. Speaker: Order, order. Shri P. C. Borooah.

Shri P. C. Borooah (Sibsagar): Even after three Five Year Plans, we find that the rivers in eastern India continue to remain as the rivers of sorrow, misery and suffering despite the promise and the potential inherent in them to become rivers of plenty, abundance and merriment for mankind. May I know what positive steps, concrete steps, Government propose to take in the Fourth Plan to be carried out from the Central sector for their transformation from misery to abundance and, if so, the details thereof?

Shri Fakhruddin Ahmed: I have indicated in detail what measures we propose to take to mitigate this.

Mr. Speaker: Shrimati Ramdulari Sinha.

Shri P. C. Borooah: What are the concrete measures to be taken from the Central sector?

Mr. Speaker: He has given that in detail.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : क्या यह सही है कि गंडक, बागमति, लखन दई, कमला बालान और अथवारा ५५ आ५० रिवर्ज़ में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

इस साल बाढ़ की विभिषिका ने जो ताण्डव रूप दिखलाया है वह 1954 से भी अधिक भयंकर है? यह वहां की जनता भी कह रही है। 1954 की बाढ़ के सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं पटने में जाकर यह कहा था कि 1954 की जैसी बाढ़ पिछले सत्तर वर्षो में नहीं आई है। इतनी भीषण बाढ़ पिछले सत्तर वर्षों में कभी नहीं आई है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की भयंकर बाढ़ वहां पर आज आई है। ऐसी जब स्थिति है तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपने सिचुएशन का रिएसेसमेंट करके कोई शीघ्रता से कदम उठाने का निर्णय किया है ताकि गंडक प्रोजेक्ट तुरन्त पूरी हो सके ?

उसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इन पर तटबंधों और कलवर्टस की व्यवस्था हो सके इसके बारे में भी आपने क्या कोई निर्णय किया है ? वहां के लोगों के बीच वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह प्रापरली हो सके और इन फ्लड्ज़ से वे बच सकें इसके बारे में आपने कोई प्रबन्ध किया है ? वहां जान और माल की बहुत क्षति हुई है। वहां पर नावों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। सीड भी वहां पहुंचाना है और फाडर की भी जरूरत है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है। आपने जो सहायता अभी तक दी है वह बहुत सी नाकाफी है। मैं जानना चाहती हूं इस रकम में भी आपने पर्याप्त वृद्धि करने का कोई फैसला किया है या करेंगे ?

श्री फरुद्दीन अहमद : आनरेबल मेम्बर ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कि बहुत हद तक वहां की जो हालत है उसके मुताल्लिक एक सही नक्शा उन्होंने जरूर खींचा है। मैं सिर्फ यह यकीन उनको दिलाना चाहता हूं कि गंडक पर बड़े जोर से काम जारी है और अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी हो तो उस पर सोच विचार करके जो बाकी काम है उसकी बाबत सोचा जा सकता है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मंत्री महोदय आकाशमार्ग से गए और आकाश ही से उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी गंडक जिसका उद्गम स्थान नेपाल है और जो बिहार और उत्तर प्रदेश के किनारे से होकर बहती है और जिसके एक तरफ तो चम्पारन जिला है और दूसरी तरफ देवरिया जिला है उसके तटबन्ध टूट जाने के कारण बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी भयंकर बाढ आई। देवरिया जिले में जो छतौनी स्थान है उस क्षेत्र में 27 गांव जलमग्न हो गए हैं हजारों आदमी गृहहीन हो गए हैं, भोजनहीन हो गए हैं, उनके लिए कपड़े का ठिकाना नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन स्थानों का भी क्या आपने निरीक्षण किया है और अगर किया हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने व [illegible] यता प्रदान की है ? छतौनी में जो शूगर [illegible] है, खडडा मिल है और रेलवे की जो [illegible] इन संकटग्रस्त है उनकी रक्षार्थ सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्री फरुद्दीन अहमद : आनरेबल मेम्बर को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब हम बिहार गए थे तो बिहार जाते वक्त गोरखपुर की तरफ से देवरिया जिले की तरफ भी गए थे और वहां हमने देखा जो गंडक के ज़रिये से नुकसान हुआ है। यू० पी० की चीफ़ मिनिस्टर कल या परसों आने वाली हैं। उनको किस किस्म की सहायता चाहिए इस बारे में उनसे बातचीत करके हम आगे कार्यवाही करेंगे।

———